



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1401]

नई दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 6, 2008/आश्विन 14, 1930

No. 1401]

NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 6, 2008/ASVINA 14, 1930

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2008

का.आ. 2406(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

“आदेश

श्री नवाब काजिम अली खान, विधान सभा सदस्य, उत्तर प्रदेश (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् याची कहा गया है) द्वारा भारत की राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन सुश्री जयाप्रदा, संसद् सदस्य (लोक सभा) (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् प्रत्यर्थी कहा गया है) के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (ग) के निबंधनों में तारीख 21 अप्रैल, 2008 की एक याचिका प्रस्तुत की गई है जिसमें उनकी अभिकथित निरहता के प्रश्न को उठाया गया है;

और याची द्वारा उसकी याचिका में यथाकथित मामले के तथ्य यह हैं कि मद्रास उच्च न्यायालय ने, अपने तारीख 4-3-2008 के आदेश में यह अधिनिर्धारित किया है कि सुश्री जयाप्रदा सितंबर, 2006 से दिवालिया हो गई हैं और इस प्रकार सुश्री जयाप्रदा ने दिवालियापन के आधार पर निरहता उपगत की है;

और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन तारीख 29 अप्रैल, 2008 के एक निर्देश के अधीन इस प्रश्न के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या सुश्री जयाप्रदा, संसद् सदस्य (लोक सभा) संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (ग) के अधीन संसद् सदस्य (लोक सभा) का सदस्य होने के लिए निरहता के अध्वधीन हो गई थी;

और निर्वाचन आयोग ने याची को दो सूचनाएं जारी की थी, एक तारीख 19-05-2008 की तथा दूसरी तारीख 23-06-2008 की, जिसमें उन्हें अपेक्षित ब्यौरे तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने का समय दिया

गया था। याची ने पहली सूचना का कोई उत्तर नहीं दिया था, तथापि, दूसरी सूचना के उत्तर में याची ने अपने तारीख 27-06-2008 के पत्र द्वारा एक प्रेस क्लिपिंग (द टाइम्स ऑफ इंडिया तारीख 5-3-2008) की प्रति उपलब्ध कराई और यह कथन किया कि उन्हें उक्त समाचार पत्र से यह पता चला था कि सुश्री जयाप्रदा ने सितंबर, 2006 में मद्रास उच्च न्यायालय में दिवालिया हो जाने का दावा किया था तथा इसके अतिरिक्त, उनके पास अपनी याचिका का समर्थन करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज नहीं था;

और याची द्वारा प्रस्तुत प्रेस क्लिपिंग यह रिपोर्ट करती है कि सुश्री जयाप्रदा को अंतर्वर्तित करने वाले किसी संपत्ति संबंधी मामले में न्यायालय की सुनवाई से यह तथ्य सामने आया है कि सुश्री जयाप्रदा सितंबर, 2006 से दिवालियापन की स्थिति में थी। यह रिपोर्ट सुश्री जयाप्रदा को दिवालिया घोषित करने वाले किसी न्यायालय आदेश का उल्लेख नहीं करती है, और इसलिए इस विषय में निर्वाचन आयोग द्वारा पूर्व में लिया गया मत यह है कि प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 के अधीन केवल किसी सक्षम न्यायालय द्वारा यह घोषित किए जाने पर ही कि कोई व्यक्ति दिवालिया है, निरहंता आकर्षित होती है;

और निर्वाचन आयोग ने यह संप्रेक्षण किया है कि अभिकथन ऐसे अस्पष्ट हैं कि निर्वाचन आयोग यह अवधारित करने की स्थिति में भी नहीं है कि वह सुसंगत जानकारी या दस्तावेज किस प्राधिकरण अथवा न्यायालय से प्राप्त करे। याची द्वारा निर्दिष्ट प्रेस रिपोर्ट, सुश्री जयाप्रदा की अभिकथित निरहंता के मामले में और कार्यवाही करने के लिए प्रथमदृष्ट्या मामला भी प्रस्तुत नहीं करती है;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि याची द्वारा प्रस्तुत की गई याचिका महत्वहीन है और वह प्रारंभ से ही नामंजूर किए जाने की दायी है;

अतः, अब, मैं, प्रतिभा देवीसिंह पाटील, भारत की राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह अभिनिर्धारित करती हूं कि श्री नवाब काज़िम अली खान द्वारा प्रस्तुत याचिका महत्वहीन है और इसलिए उसे प्रारंभ से ही नामंजूर किया जाता है।

18 सितम्बर, 2008

भारत की राष्ट्रपति"

[फा. सं. एच 11026(3)/2008-वि. II]

डॉ. संजय सिंह, संयुक्त सचिव एवं विधायी परामर्शी

उपाबंध

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन

अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

2008 का निर्देश मामला सं. 4

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

निर्देश : भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ग) के अधीन सुश्री जयाप्रदा, संसद सदस्य (लोक सभा) की अभिकथित निरहंता।

राय

भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से तारीख 29.04.2008 का एक निर्देश प्राप्त हुआ था, जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग से राय मांगी गई है कि क्या सुश्री जयाप्रदा भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ग) के अधीन संसद सदस्य (लोक सभा) होने के लिए निरहंता के अधीन हो गई हैं।

2. पूर्वोक्त प्रश्न श्री नवाब काज़िम अली खान, विधान सभा सदस्य, उत्तर प्रदेश द्वारा राष्ट्रपति को भारत के संविधान के अनुच्छेद 103(1) के अधीन प्रस्तुत तारीख 21.04.2008 की याचिका में उठाया गया था, जिसमें सुश्री जयाप्रदा को संसद् सदस्य (लोक सभा) होने के लिए निरर्थक करने की मांग की गई थी।
3. याची द्वारा उसकी याचिका में यथास्थित मामले के तथ्य यह हैं कि मद्रास उच्च न्यायालय ने, अपने तारीख 4.3.2008 के आदेश में यह अभिनिर्धारित किया है कि सुश्री जयाप्रदा सितंबर, 2006 से दिवालिया हो गई हैं। अतः, सुश्री जयाप्रदा ने दिवालियापन के आधार पर निरर्थकता उपगत की है। याची ने उसकी शिकायत के आधार के रूप में मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष न्यायालय कार्यवाहियों/आदेश को निर्दिष्ट किया है।
4. राष्ट्रपति से निर्देश प्राप्त होने पर, आयोग ने यह विनिश्चय किया कि याची से प्रश्नगत न्यायालय आदेश सहित पर्याप्त समर्थकारी दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा जाना चाहिए और उसे एक सूचना जारी की थी। तदनुसार, श्री खान को तारीख 19.05.2008 को एक सूचना जारी की गई थी, जिसमें उन्हें उनकी इस दलील/आरोप को साबित करने के लिए कि सुश्री जयाप्रदा को न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित किया गया था, 13.06.2008 तक (i) उनकी याचिका में किए गए दावे के समर्थन में पूर्ण ब्यौरे और (ii) उनकी याचिका में निर्दिष्ट मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित सभी सुसंगत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था।
5. श्री खान ने विहित समय तक आयोग की सूचना का कोई उत्तर नहीं दिया था। तथापि, आयोग ने उन्हें अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने का एक और अवसर प्रदान करने का विनिश्चय किया था। तदनुसार, 23.06.2008 को एक और सूचना जारी की गई थी, जिसमें उन्हें अपेक्षित ब्यौरे और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए 14.07.2008 तक का समय दिया गया था।
6. आयोग की तारीख 23.06.2008 की सूचना के उत्तर में, श्री खान ने अपने तारीख 27.06.2008 के पत्र द्वारा एक प्रेस क्लिपिंग (द टाइम्स ऑफ इंडिया तारीख 5.3.2008) की प्रति उपलब्ध कराई और यह कथन किया कि उन्हें उक्त समाचार पत्र से यह पता चला था कि सुश्री जयाप्रदा ने सितंबर, 2006 में मद्रास उच्च न्यायालय में दिवालिया हो जाने का दावा किया था। उन्होंने यह और सूचित किया कि उसके अतिरिक्त, उनके पास अपनी याचिका का समर्थन करने के लिए कोई अन्य दस्तावेज नहीं था।
7. संविधान के अनुच्छेद 102(1)(ग) के अधीन कोई अनुमोचित दिवालिया संसद् सदस्य होने के लिए निरर्थक है। याची द्वारा प्रस्तुत प्रेस क्लिपिंग यह रिपोर्ट करती है कि सुश्री जयाप्रदा

को अंतर्वलित करने वाले किसी संपत्ति संबंधी मामले में न्यायालय की सुनवाई से यह तथ्य सामने आया है कि सुश्री जयाप्रदा सितंबर, 2006 से दिवालियापन की स्थिति में थी। यह रिपोर्ट सुश्री जयप्रदा को दिवालिया घोषित करने वाले किसी न्यायालय आदेश का उल्लेख नहीं करती है। इस विषय में आयोग द्वारा पूर्व में लिया गया मत यह है कि प्रान्तीय दिवाला अधिनियम, 1920 के अधीन केवल किसी सक्षम न्यायालय द्वारा यह घोषित किए जाने पर भी कि कोई व्यक्ति दिवालिया है, निरर्हता आकर्षित होती है। उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि अनुच्छेद 102(1)(ग) के अधीन निरर्हता केवल तभी उपगत होती है जब दिवाला अधिनियम के अधीन किसी सक्षम न्यायालय द्वारा घोषणा की गई हो [थम्पानूर रवि बनाम चारुपारा रवि {1999 (8) एस.सी.सी. 74}]। इस मामले में, याची द्वारा प्रस्तुत प्रेस रिपोर्ट, जो कि प्रस्तुत किया गया अकेला समर्थनकारी दस्तावेज है, दिवाला अधिनियम के अधीन किसी न्यायालय आदेश को निर्दिष्ट नहीं करता है। यह दर्शित करने के लिए कोई दस्तावेज नहीं है कि न्यायालय द्वारा सुश्री जयप्रदा को दिवाला अधिनियम के अधीन दिवालिया अधिनिर्णीत करते हुए कोई घोषणा की गई थी।

8. लाभ के पद से संबंधित मामलों में, याची द्वारा आवश्यक ब्यौरे प्रस्तुत करने में असफल रहने पर आयोग ने ऐसे संबद्ध सरकारी विभाग से, जो प्रश्नगत पद पर नियुक्ति से संबंधित है, आवश्यक ब्यौरे प्राप्त करने की चेष्टा करती है। तथापि, वर्तमान मामले में, आरोप ऐसे अस्पष्ट हैं कि आयोग यह अध्वारित करने की स्थिति में नहीं है कि वह सुसंगत जानकारी या दस्तावेज किस प्राधिकरण अथवा न्यायालय से प्राप्त करे। जब कोई व्यक्ति, किसी न्यायालय के निर्णय के आधार पर किसी संसद् सदस्य की निरर्हता का मुद्दा उठाता है तो याची से यह आशा की जाती है कि वह अपने दावे के समर्थन में एक न्यूनतम अपेक्षा के रूप में यदि निर्णय की प्रति प्रस्तुत नहीं कर सकता है तो कम से कम न्यायालय की कार्यवाहियों के न्यूनतम ब्यौरे तो प्रस्तुत करेगा। इस मामले में ऐसे न्यूनतम ब्यौरे भी लापता हैं। याची ने यह कथन किया है कि उसके द्वारा जिस अकेले दस्तावेज का अवलंब लिया गया है, वह प्रेस रिपोर्ट है। याची द्वारा निर्दिष्ट प्रेस रिपोर्ट, सुश्री जयप्रदा की अभिकथित निरर्हता के मामले में आगे और कार्यवाही करने के लिए प्रथमदृष्ट्या मामला भी प्रस्तुत नहीं करती है।

9. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, वर्तमान मामले में राष्ट्रपति से प्राप्त निर्देश को तदनुसार भारत निर्वाचन आयोग की इस राय के साथ लौटाया जाता है कि याची द्वारा की गई याचिका महत्वहीन है और वह प्रारंभ से ही नामंजूर किए जाने की दायी है।

10. आयोग के तीसरे सदस्य डा. एस.वाई. कुरैशी ने भी, जो इस समय छुट्टी पर विदेश में हैं, इस राय पर सहमति दी है।

ह0/-

(मबीन बी0 घावला)
निर्वाचन आयुक्त

ह0/-

(एन0 गोपालास्वामी)
मुख्य निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली

तारीख : 30 जुलाई, 2008

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2008

S.O. 2406(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

“ORDER

Whereas a petition dated the 21st April, 2008 raising the question of alleged disqualification in terms of sub-clause (c) of clause (1) of article 102 of the Constitution in respect of Ms. Jayaprada, Member of Parliament (Lok Sabha) (hereinafter referred to as the respondent) under clause (1) of article 103 has been submitted to the President of India by Shri Nawab Kazim Ali Khan, MLA, Uttar Pradesh (hereinafter referred to as the petitioner);

And whereas the facts of the case as stated by the petitioner in his petition are that the Madras High Court, in its Order dated 4.3.2008, has held that Ms. Jayaprada has been insolvent since September, 2006 and hence she has incurred disqualification on the ground of insolvency;

And whereas the opinion of the Election Commission of India has been sought by the President under a reference dated the 29th April, 2008 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Ms. Jayaprada, Member of the Parliament (Lok Sabha), has become subject to disqualification for being a Member of Parliament (Lok Sabha) under sub-clause (c) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas the Election Commission has issued two notices, one dated 19.05.2008 and another dated 23.06.2008, to the petitioner giving him time to furnish requisite details and documents. The petitioner did not respond to the first notice however in response to the second notice, the petitioner *vide* his letter dated 27.06.2008 provided a copy of a press clipping (The Times of India, dated 5.3.2008) stating that from the said news item he learnt that Ms. Jayaprada had claimed insolvency in the Madras High Court in September, 2006 and besides this, he had no further document to support his petition;

And whereas the press clipping produced by the petitioner reports that the court hearing over some property matter involving Ms. Jayaprada, had brought to the light the fact Ms. Jayaprada was in a state of insolvency since September, 2006. This report does not say about any Court order declaring Ms. Jayaprada an insolvent and therefore, the view taken by the Election Commission in the past on this subject is that disqualification is attracted only following a declaration by a competent Court under the Provincial Insolvency Act, 1920, that a person is an insolvent;

And whereas the Election Commission has observed that the allegations are so vague that the Election Commission is not in a position even to determine the authority or Court from which to seek the relevant information or documents. The press report referred to by the petitioner does not make out even, *prima facie*, a case for proceeding further in the matter of alleged disqualification of Ms. Jayaprada;

And whereas the Election Commission has given its opinion (*vide* Annexure) that the petition made by the petitioner is frivolous and liable to be rejected *in limine*;

Now, therefore, I, Pratibha Devisingh Patil, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that the petition made by Shri Nawab Kazim Ali Khan is frivolous and, therefore, rejected *in limine*.

18th September, 2008

President of India

[F. No. II-11026(3)/2008-Leg.II]

Dr. SANJAY SINGH, Jt. Secy. and Legislative Counsel

ANNEXURE
ELECTION COMMISSION OF INDIA
NIRVACHAN SADAN

Ashoka Road, New Delhi-110 001

Reference Case No. 4 of 2008

[Reference from the President under Article 103(2) of the Constitution of India]

In re : Alleged disqualification of Ms. Jayaprada, M.P. (Lok Sabha) under Article 102 (1)(c) of the Constitution of India.

OPINION

A reference dated 29.4.2008, was received from the President, seeking the opinion of the Election Commission under Article 103(2) of the Constitution of India, on the question whether Ms. Jayaprada, has become subject to disqualification for being Member of Parliament (Lok Sabha) under Article 102 (1)(c) of the Constitution of India.

2. The above question arose on the petition dated 21.4.2008, submitted by Shri Nawab Kazim Ali Khan, MLA, Uttar Pradesh to the President, under Article 103(1) of the Constitution of India, seeking disqualification of Ms. Jayaprada, for being a Member of Parliament (Lok Sabha).

3. The facts of the case as stated by the petitioner in his petition are that the Madras High Court, in its order dated 4.3.2008, has held that Ms. Jayaprada has been insolvent since September, 2006. Hence, Ms Jayaprada has incurred disqualification on the ground of insolvency. The petitioner has referred to the Court proceedings/order before the Madras High Court as the basis of his complaint.

4. On receipt of the reference from the President, the Commission decided that the petitioner should be asked to produce adequate supporting documents including the Court order in question and issued a notice to him. Accordingly, a notice dated 19.5.2008 was issued to Shri Khan to furnish, by 13.6.2008, (i) the complete details in support of the claim in his petition, and (ii) all relevant information/documents including certified copy of the judgement of the Madras High Court referred to in his petition, to substantiate his contention/allegation that Ms. Jayaprada had been declared insolvent by the Court.

5. Shri Khan did not respond to the notice of the Commission by stipulated time. However, the Commission decided to give him another opportunity to furnish the requisite information. Accordingly, another notice was issued on 23.6.2008 giving him time upto 14.7.2008 to furnish the requisite details and documents.

6. In response to the Commission's notice dated 23.6.2008, Shri Khan, vide his letter dated 27.6.2008, provided a copy of a press clipping (The Times of India, dated 5.3.2008) stating that from the said news item he learnt that Ms. Jayaprada had claimed insolvency in the Madras High Court in September, 2006. He further informed that besides this, he had no other document to support his petition.

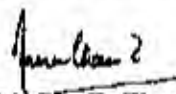
7. Under Article 102(1)(c) of the Constitution, an undischarged insolvent is disqualified to be a member of the Parliament. The press clipping produced by the petitioner reports that the court hearing over some property matter involving Ms. Jayaprada, had brought to light the fact that Ms. Jayaprada was in a state of insolvency since September, 2006. This report does not say about any Court order declaring Ms. Jayaprada an insolvent. The view taken by the Commission in the past on this subject is that disqualification is attracted only following a declaration by a competent court under the Provincial Insolvency Act, 1920, that a person is an insolvent. The Supreme Court has also held that disqualification under Article 102(1)(c) arises only on a declaration by the competent court under the Insolvency Act [Thampanoor Ravi Vs. Charupara Ravi {1999 (8) SCC 74}]. In the present case, the press report produced by the petitioner which is the only supporting document produced, does not refer to any court order under the Insolvency Act. There is no document to show that there was any declaration by the Court adjudging Ms. Jayaprada an insolvent under the Insolvency Act.

8. In matters relating to office of profit, in the event of the petitioner failing to furnish necessary details, the Commission has tried to obtain the same from the Government Department concerned, which deals with appointment to the office in question. In the present case, however, the allegations are so vague that the

Commission is not in a position even to determine the authority or Court from which to seek the relevant information or documents. When a person raises the issue of disqualification of a Member of Parliament based on a court judgment, the petitioner is expected to furnish at least the minimum details of the court proceedings, if not a copy of the judgment as a minimum requirement in support of his claim. Here, even these minimum details are missing. The petitioner has stated that the only document relied upon by him is the press report. The press report referred to by the petitioner does not make out even, *prima facie*, a case for proceeding further in the matter of alleged disqualification of Ms. Jayaprada.

9. In view of the above, the reference received from the President in the present case is, accordingly, returned with the opinion of the Election Commission of India, that the petition made by the petitioner is frivolous and liable to be rejected in limine.

10. Dr. S.Y.Quraishi, the third member of the Commission, who is presently abroad on leave, has also concurred with this opinion.


(Navin B. Chawla)
Election Commissioner


(N. Gopalaswami)
Chief Election Commissioner

Place : New Delhi.
Dated : 30th July, 2008